दादरा एवं नगर हवेली के 60वें

मुक्ति दिवस के अवसर पर

प्रशासक

दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली का

अभिभाषण

2 अगस्त, 2013

माननीय संसद सदस्य श्री नटुभाई जी. पटेल ,

जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री दीपक प्रधान,

सिलवासा नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा कुमारी. चंदनबेन एस. डेलकर,

पुलिस महानिरीक्षक श्री राजेश खुराना,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश आर. देशमुख ,

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के सभी सचिव,

समाहर्ता, दादरा एवं नगर हवेली,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री आर. एस. पाटिल,

पूर्व सांसद श्री एस. जे. गवली

दादरा एवं नगर हवेली के स्वतंत्रता सेनानी,

सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण,

निर्वाचित प्रतिनिधि,

सरकारी अधिकारीगण,

यहाँ उपस्थित उद्योगपतिगण,

मीडिया के प्रतिनिधिगण,

भाईयों और बहनों,

प्यारे बच्चों,

दादरा एवं नगर हवेली के 60 वें मुक्ति दिवस पर मैं इस संघ प्रदेश की आम जनता को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ । मैं उन सभी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से इस संघ प्रदेश की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

-- भारत की मुख्य धारा से जुड़ने के पश्चात इस प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । हमें बहुत गर्व है कि यह प्रदेश सभी प्रकार से शांति और सद्भावना का साक्षी है । इस प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 2.2 लाख से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.43 लाख हो गयी जिससे यहाँ की **Density** 400 व्यक्ति **Per Square Kilometer** से बढ़कर 700 व्यक्ति **Per Square Km** हो गयी । औद्योगिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों की तीव्र वृद्धि के कारण इस प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क एवं पुल, विद्युत उप केंद्र, जल आपूर्ति, साफ सफाई, जनसंख्या नियंत्रण तथा अन्य विश्व स्तरीय विकास की आवश्यकता है । हम इस प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की चुनौती का सामना करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं ।

<u>दौरा कार्यक्रम</u> :-

मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कुछ महीनों में दोनों माननीय गृह मंत्री तथा माननीय गृह राज्य

मंत्री ने इस प्रदेश में दौरा किया और हमारे विकास तथा प्रगति के क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की प्रशंसा की ।
उनके इस दौरों से हमें उन सभी नई परियोजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिला जिन्हें हम करा रहे हैं, साथ ही साथ उन विषयों का ध्यान आकर्षित कराने का अवसर मिला जिन्हें भारत सरकार द्वारा हल किए जाने की आवश्यकता है । मैंने गृह सचिव से भी जल्दी से जल्दी इस संघ प्रदेश के दौरे के लिए निवेदन किया है ।

<u>योजना आबंटन और व्यय :</u>

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2012 13 में 564 करोड़ रुपये से चालू वर्ष 2013 14 में 672 करोड़ रुपये हमारी योजना निधि में वृद्धि की है । मुख्य क्षेत्रों के लिए आवंटन इस प्रकार है : ऊर्जा क्षेत्र 173 करोड़ रुपये, मार्ग तथा पुल 145 करोड़ रुपये, शिक्षा 86 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य 64 करोड़ रुपये, घर तथा शहरी विकास 32 करोड़ रुपये तथा जल आपूर्ति तथा सिंचाई 44 करोड़ रुपये है । पिछले वर्ष हमने आबंटित **funds** का 100 प्रतिशत व्यय किया और इस वर्ष भी हम उसी प्रकार सुनिश्चित कराते हुए नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं । संघ प्रदेश का कुल राजस्व वर्ष 2012 13 में 613 करोड़ रुपये था । हमें पता चला है कि वर्ष 2012 13 में संघ प्रदेश से संचालित केंद्रीय आबकारी

की कुल राशि 5000 करोड़ रुपये से अधिक थी, जबकि आयकर लगभग 250 करोड़ रुपये था । इसका मतलब है कि हमारे संघ प्रदेश ने भारत सरकार को पिछले वर्ष 5,800 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया । इसलिए मुख्य परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ हमारे राजस्वों पर विचार कराते हुए, हम आगामी वर्ष में अधिक **funds** आबंटन के लिए भारत सरकार से अनुरोध करेंगे ।

<u>कृषि</u> :

हमारे ग्रामीण आदिवासियों की मुख्य गतिविधि कृषि है, इसलिए हमने इस क्षेत्र को महत्व देना जारी रखा है । वर्ष 2012 13 के दौरान हमने 1300 **MT** से अधिक रासायनिक खाद्य लगभग 9000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छोटे तथा **Marginal** किसानों को वितरित किए तथा 44 **MT** उत्तम पैदावार के बीज लगभग 1900 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के छोटे तथा **Marginal** किसानों को वितरित किए । पशुपालन क्षेत्र के अंतर्गत छोटी डेयरी ईकाईयों तथा **Integrated Dairy** विकास परियोजना की स्थापना की गई । पिछले वर्ष ऐसी 18 **Dairy** ईकाईयों को स्थापित किया गया और इस वर्ष 20 से अधिक ईकाईयों को स्थापित करने की योजना है । **IDDP** के तहत 14 ग्राम **Dairy Cooperatives** को संचालित किया गया है, जो 350 लाभार्थियों द्वारा विशेष रूप से चलाये जा रहे हैं । इस वर्ष 5 अतिरिक्त **Village Cooperatives** को स्थापित किया

जा रहा है । इन लाभों में वृद्धि उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष योजना के **norms** को भी संशोधित किया गया है ।

<u>सड़क एवं पुल:-</u>

हमारे प्रयासों के कारण भारत सरकार ने इस संघ प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए पहली बार अधिसूचना जारी की है । यह राष्ट्रीय राजमार्ग वापी से दादरा – पिपरीया – सिलवासा – उल्टन फलिया – भूरकुड फलिया – खड़ोली सुरंगी – वेलुगाम – सूत्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 8 तक होगा । इससे हमारी--औद्योगिक ईकाईयों को तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बहुत लाभ मिलेगा । हमने अथाल, रखोली, पिपरीया, डोकमरडी, मोरखल तथा करचौंड पर महत्वपूर्ण पुलों का भी निर्माण कार्य आरम्भ किया है । अप्रैल,2013 से हमने 06 अतिरिक्त पुलों के निर्माण कार्य को लिया है, जिसके लिए **tender** प्रक्रिया की जा रही है । हम सभी **Major District Roads** को चौड़ा करने के भी योजना बना रहे हैं । हमने खेरडी – तलासरी रोड को शीघ्र चौड़ा करने तथा सुधार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध किया है ताकि मुंबई की तरफ यात्रा में सुधार आये । इसके अतिरिक्त सिलवासा के चारों ओर **Ring Road** के निर्माण के लिए हमारा प्रस्ताव भारत सरकार की अंतिम मंजूरी के लिए पड़ा हुआ है ।

ऊर्जा :

हम सबसे उचित मूल्यों पर **quality power** उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं । इस उद्देश्य से हमने वाघधरा पर 2 x 20 **MVA** 66/11 **KV Sub-station** की स्थापना की है । वेलुगाम – कला और पिपरीया पर 66/11 **KV Electric Sub-station** पर कार्य चल रहा है । हम सिलवासा नगरपालिका के क्षेत्र में **Underground cables** बिछाने के अतिरिक्त **Smart Grid** लगाने की प्रक्रिया में है । इसके अलावा इस प्रदेश में 3 **MW Solar Plant** 28 करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए **tender** आमंत्रित किये जा रहे हैं । विभाग के **Computerisation** की प्रक्रिया भी चल रही है ।

स्वास्थ्य :

हम इस प्रदेश के निवासियों के लिए सबसे अच्छी जन स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं । स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता के अंतर्गत **EFC** की बैठक ने श्री विनोबाभावे सिविल अस्पताल के **Upgradation** के लिए **in-principle** मंजूरी दे दी है । इस **Project** की लागत 226 करोड़ रुपये अनुमानित है । हम सितम्बर,**2013** में नर्सिंग कॉलेज की भी शुरुआत कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में **basic** स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की पुरानी माँग को पूरा करने के लिए रखोली में अप्रैल से तथा

दादरा में जून में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आरंभ किया है । 108 **Emergency Medical Response Service** के अप्रैल 2012 में आरंभ होने से अब तक 19,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिल चुका है । **Medical Emergency** सेवाओं को उपलब्ध कराने के विषय में हमने भारत में अपनी तरह की लगभग पहली 104 **toll-free number** की सेवा आरंभ की है जिसमें कोई भी व्यक्ति **telephone** पर **Medical** सलाह प्राप्त कर सकता है । संघ प्रदेश प्रशासन ने नये **Medical College** की स्थापना की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके--लिए- इसकी प्रक्रिया में हमारी सहायता के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है ।

<u>जल आपूर्ति :</u>

पीने के पानी की व्यवस्था करना हमारे लिए एक प्राथमिकता बनी हुई है । 27 करोड़ रुपये की लागत पर सिलवासा शहर के लिए सिलवासा नगरपालिका की **Water supply Scheme** को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा । जिला पंचायत द्वारा कार्यान्वित की जा रही मान्दोनी और दूधनी के लिए **Piped water supply Scheme** को भी अगले कुछ महीनों में पूरा कर दिया जायेगा । 255 करोड़ रुपये की लागत पर अन्य क्षेत्रों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए **Integrated Water Management Scheme** अब भारत सरकार की अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा में है ।

Sewerage तथा स्वच्छता :

पीने के पानी के साथ स्वच्छता एक स्वस्थ अस्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू है। संपूर्ण संघ प्रदेश के लिए एक व्यापक **Solid Waste Management Project** को तैयार किया गया है और आगामी वर्ष में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा । हमने 21 करोड़ रुपए की लागत पर सिलवासा के लिए **Underground Sewerage Project** की मंजूरी दी है जिसे **OIDC** द्वारा किया जा रहा है । हमने इस प्रदेश के अन्य **Census towns** में **Sewerage** सुविधाओं के लिए भी योजना बनाना आरंभ कर दिया है ।

शिक्षा :

प्रशासन के निरंतर तथा ठोस प्रयासों से संघ की कुल साक्षरता दर वर्ष 2001 में 57.63 प्रतिशत से वर्ष 2011 में 77.65 प्रतिशत तक पहुँच गयी है । विभिन्न स्थानों पर सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ **Primary School** इमारत के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लिया गया है । मैंने अधिकारियों में सभी सरकारी स्कूलों को आबंटित किया है । सभी अधिकारियों ने अपने अपने स्कूलों का दौरा किया और बुनियादी ढाँचे में **Gaps** को सूचीबद्ध किया । अब हम आगामी छः महीनों के अंदर उन **Gaps** को पूरी तरह से भर देंगे ।

फलांडी और सीली में दो नये गुजराती माध्यम हाई स्कूल, दादरा, खानवेल तथा नरोली में तीन नये अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल तथा रखोली में **Science stream** के साथ एक **Higher Secondary School** का प्रारंभ किया गया है । सात माध्यमिक स्कूल इमारतों को निर्मित करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है।

सिलवासा में पहली बार सरकारी कॉलेज जुलाई, 2011 को प्रारंभ किया गया था। अब इसमें **Arts, Commerce** तथा **Science stream** में 1100 से भी अधिक विद्यार्थी हैं । कॉलेज के लिए नई इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है । अब हमने इस कॉलेज का नया नाम " सिलवासा कॉलेज " रखने का निर्णय लिया है ।

<u>सिंचाई :</u>

सिंचाई के लिए **Check dam** तथा लघु सिंचाई जैसी योजनाओं के अतिरिक्त जिला पंचायत ने मोटा राँधा में कोलक नदी पर **Check dam -cum-causeway** का निर्माण कार्य आरंभ किया है जो इस प्रदेश के निवासियों की लंबे समय से माँग थी । जून,**2014** तक इस **Project** के पूरा होने पर पड़ौसी राज्यों के घरमपुर और नासिक जिला के लिए आवश्यक सड़क उपलब्ध होगी और अतिरिक्त 160 एकड़ कृषिक भूमि को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ।

<u>पर्यटन :</u>

हमने महसूस किया है कि आने वाले वर्षों में इस प्रदेश के लिए सबसे अधिक क्षमता रखने वाला क्षेत्र पर्यटन है । इसलिए हम इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं । अथाल में दमणगंगा नदी पर **River front development** का महत्वपूर्ण **Project** की पूरी **planning** की जा चुकी है और 15 करोड़ रुपये की लागत पर **Project** के **first phase** के लिए **tender** जारी किया गया है । इसके अतिरिक्त हमने 5 करोड़ रुपये की लागत पर दूधनी **lake front development** का कार्य भी लिया है । हमने पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षणों को उपलब्ध कराने के लिए अथाल में **River front Project** के हिस्से के रूप में " सिलवासा हाट " तथा पिपरिया में **State Museum** स्थापित करने के लिए नई परियोजना को भी लिया है । हमने दादरा गार्डन का महत्वपूर्ण विकास और लुहारी पर एक नये विज्ञान केंद्र के निर्माण की भी योजना बनाई है । हम आशा करते हैं कि इन अतिरिक्त सुविधाओं से न केवल पर्यटकों को आकर्षित करने में हमें सहायता मिलेगी बल्कि इस प्रदेश में हम उनको एक दो अतिरिक्त दिन रहने के लिए लोभित कर सकेंगे ।

<u>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :</u>

वर्तमान में लगभग 12,000 **BPL** परिवार **Public distribution Scheme** का लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर प्रति मास 32 **Kg** चावल, 3 **Kg** गेहूँ एवं 5 लीटर **Kerosine** हर महीने उपलब्ध करवाया जाता है ।

अंत्योदया अन्न योजना के अंतर्गत 5000 परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर 33 किलोग्राम चावल और 02 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह का लाभ मिल रहा है । अन्नपूर्णा योजना के तहत 380 लाभार्थियों को निःशुल्क 10 Kg चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने **National Food Security Ordinance** को हाल ही में **notify** किया है जिसके द्वारा 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने का उद्देश्य है । सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल को लागू करने के लिये हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

<u>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण :-</u>

इस प्रदेश में एकीकृत बाल विकास परियोजना **(ICDS)** को 219 आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 49 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जहाँ 21,000 से अधिक बच्चों तथा 3,300 महिलाओं को लाभ मिल रहा है । 10,000 के करीब आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनाओं के द्वारा लाभ पहुँचाया जा रहा है ।

सरस्वती साधना योजना के अंतर्गत कक्षा 8 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति छात्राओं को निःशुल्क साइकिल

वितरित की जाती हैं । पिछले वर्ष 1785 साइकिलें वितरित की गई । चालू वर्ष में हमने कक्षा 8वीं की सभी 3500 छात्राओं को निःशुल्क साईकिलें देने का फैसला किया है जिसका उद्देश्य है कि छात्रायें **High School** के प्रवेश पर स्कूल न छोड़ें । हम **minorities** विद्यार्थियों को **Pre-matric** तथा **Post-matric scholarship** दे रहे हैं जिसमें पिछले वर्ष 266 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया । हमने इस प्रदेश में महिलाओं, बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है ।

<u>श्रम कल्याण :</u>

उद्योग, सिविल निर्माण, परिवहन की तरह विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत **Labour force** बड़ी संख्या में होने की वजह से, यह महत्वपूर्ण है कि श्रमिक एवं उनके परिवारों के रक्षण को प्राथमिकता दी जाये । **Workmen's Compensation Act,** 1923 के अंतर्गत 1.39 करोड़ रु. की राशि वसूली गई और 33 घायल कर्मगार एवं 13 बीमार कर्मगार के 36 **dependents** को भुगतान किया गया, जबकि **Industrial Disputes Act,** 1947 के अंतर्गत 209 श्रमिकों के मामले निपटाए गए और रु. 70.23 लाख कि राशि वसूली करके 432 श्रमिकों को भुगतान किया गया ।

<u>वानिकी</u>

संघ प्रदेश में तेजी से औद्योगीकरण को देखते हुए वन संरक्षण की भूमिका अति महत्वपूर्ण है । वर्ष 2012 13 के दौरान 200 **Hect. degraded** वन क्षेत्र को समृद्ध किया गया और 17 किलोमीटर सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया । सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए 5 लाख बीजों को वितरित किया गया । वन विभाग ने पर्यटन से संबंधित बहुत सी परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । पिछले साल दिसंबर में वाघचौड़ा पर **Panaromic View Point** और **Chauvedha Natural Trail** को विकसित किया गया गया । माननीय राज्य गृह मंत्रीजी के दौरे के समय प्रभावशाली प्रकृति -परिचय केंद्र खानवेल का उनके द्वारा उदघाटन किया गया । यह एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन गया है । हाल ही में, हमने खानवेल में **Butterfly Park** बनाया है । सिलवासा के बाल उद्यान में **Musical fountain, Waterfall, doll house** और बेहतर **lawn** उपलब्धि द्वारा विकसित किया जा रहा है ।

<u>ग्रामीण विकास :</u>

हमने ग्रामीण विकास में भी प्रगति की है । पिछले एक साल में ग्राम पंचायतों द्वारा 43 **Km** ग्रामीण मार्ग का निर्माण किया गया । ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्र में गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा 955 व्यक्तिगत घरों में शौचालय का निर्माण किया गया । **MGNREGA** के अंतर्गत 43000 श्रम

दिवस **generate** करके वर्ष 2012 13 के दौरान 1.31 करोड़ रुपये व्यय किये गये । वर्ष 2012 13 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 108 नए घरों का निर्माण किया गया और 276 नए घरों का निर्माण कार्य प्रगतिमान है । स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 101 लाभार्थियों को स्व रोजगार गतिविधियाँ शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ।

<u>कानून एवं व्यवस्था :</u>

प्रदेश में कानून और व्यवस्था भी नियंत्रण में है । **Heinous** अपराधों के तहत दर्ज मामलों की संख्या में पहले से कमी है । अपराधों की रोकथाम और **tracking** के लिए सिलवासा में विभिन्न स्थानों पर **CCTV Camera** लगाए गए हैं । हम शीघ्र तीन **Out posts** दूधनी, मांदोनी और सिंदोनी में शुरू करने जा रहे हैं ।

सायली में नया पुलिस प्रशिक्षण स्कूल का माननीय गृह मंत्री जी द्वारा **April, 2013** में उद्घाटन किया गया । इस स्कूल में हमारे पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के-लिए उत्कृष्ट सुविधा है ।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी</u>

हमने जनता को समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए समय सुधीनी सेवा के नाम से एक **landmark IT project** शुरू किया है । मई 2013 में 31 सेवाओं को और पिछले महिने

अतिरिक्त 31 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है । हम एक **Data Centre** और एक **Wide Area Network** सहित, हमारे **e-governance projects** के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना पर कार्य कर रहें हैं । हमें प्रदेश में 11 **Common Service Centre** (सामान्य सेवा केन्द्रो) की स्थापना करने जा रहें है जहाँ बहुत सी सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे जनता को उपलब्ध हो जायेगी और ऐसी सेवाओं के लिए जनता को अलग-अलग विभागों में नहीं जाना पड़ेगा । **Land records** का **digitisation** पूरा हो चूका है और **Computerised** 7/12 जारी करना शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है ।

<u>जिला पंचायत :-</u>

जिला पंचायत द्वारा विभिन्न अन्य परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है । वर्ष 2012 13 के दौरान जिला पंचायत द्वारा 44,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें, नोट बुक और **Uniform** देकर लाभान्वित किया गया जबकि 2013 14 के दौरान 48,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है । **Mid-day meal Scheme** के अंतर्गत पिछले साल 36,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया जो 2013 14 के दौरान 39,000 से अधिक विद्यार्थियों तक बढ़ने की संभावना है । इस योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला खाना देने के लिए अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित की जा रही है ।

प्रदेश में सिंचाई सुविधा में सुधार के लिए विभिन्न स्थानों में 45 मुख्य/लघु **Check dam,** 3 **lift irrigation schemes** और 15 **Ponds** का इस साल निर्माण किया जा रहा है ।

<u>सिलवासा नगर पालिका परिषद :</u>

सिलवासा नगर पालिका परिषद ने 36 करोड़ रुपये की लागत पर महत्वपूर्ण परियोजनायें ली हैं, जैसे कि नगरपालिका भवन का निर्माण, नगरपालिका मार्केट का पुनः विकास, स्ट्रीट लाईट उपलब्ध कराने के अलावा पिपरीया नदी के विकास की परियोजना, शहर में फूटपाथ का विकास और **Storm water drainage** निर्माण शामिल हैं । भारी बारीश के दौरान शहर में बहुत सी जल भराव की शिकायतों में कमी का श्रेय सिलवासा नगर पालिका परिषद को दिया जाना चाहिए, जहाँ मुख्य नालों की सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायत का भी योगदान रहा है ।

-- -

<u>OIDC</u>

OIDC प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शाखा है । प्रशासन, पुलिस, सिलवासा नगर पालिका परिषद और **MPLAD** के लिए विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के अलावा, सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत, **OIDC,** सामाजिक क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है । प्रशासन द्वारा छात्रावासों में चलाए जा रहे **Mid-day meal scheme** के सभी बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाता है । इस उद्देश्य के

लिए प्रति वर्ष 20 लाख रुपये की राशि भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को दी जाती है । इसके अलावा **OIDC** प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को प्रतिमास 4000 रुपये की पेंशन भी वितरित करता है । रुपये 5000/-, 4000/-, 3000/ क्रमशः दसवीं और बारहवी कक्षा में प्रथम तीन अव्वल रहने वाले छात्र को नकद पुरस्कार दिया जाता है ।

" संकल्प " – सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी पहल :

आप जानते ही हैं, प्रदेश में 3000 से अधिक उद्योग है । बहुत सी औद्योगिक ईकाईयाँ पहले से ही स्वैच्छिक आधार पर उनके आस पास के स्थानीय क्षेत्र में सामाजिक सेवा प्रदान कर रही है । हमारा यह मानना है कि औद्योगिक ईकाईयों, जिस समाज में वह कार्य करती हैं, उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अधिक उत्साह दिखाना आवश्यक है । इसलिए हमने एक अनूठी परियोजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत सभी 70 गाँवों के 515 पाड़ों को एक न एक औद्योगिक ईकाई द्वारा अपनाया जाएगा । आज, हम इस पहल को " संकल्प " का नाम दे रहे हैं । यानी प्रत्येक औद्योगिक इकाई एक विशिष्ट रूप से कम से कम एक गाँव या पाड़े को मदद करने का संकल्प लें । हमने एक रूपरेखा तैयार की है जिसके अंतर्गत औद्योगिक ईकाईयाँ आगे आ रही है और स्वेच्छा से **(Voluntary basis** से) इस कार्यक्रम में अपना नामांकन करवा रहे है । प्रशासन स्थानीय परामर्श के आधार पर गाँवों की आवश्यक सुविधाओं की रूप रेखा तैयार कर

रहा है । यह सुविधाएँ औद्योगिक ईकाईयों द्वारा समन्वित तरीके से प्रदान की जाएगी । मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक 16 गाँवों के 60 पाड़ों को 20 औद्योगिक ईकाईयों द्वारा अपनाये जाने का संकेत मिल चुका है । हमारा-यह लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में 50 प्रतिशत से अधिक पाड़ों को अपनाया जाए और एक वर्ष में 100 प्रतिशत गावों/ पाड़ों को अपनाया जाय । यदि हम इस पहल में सफल होते है तो सारे देश के लिए यह एक ऐसा उदाहरण बन जायेगा जहाँ उद्योग एवं समाज सद्भाव से एक साथ स्थित हैं और कार्य करते हैं ।

<u>निष्कर्ष :-</u>

मैंने अपने अभिभाषण में केवल महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और प्रशासन की पहल का उल्लेख किया है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम आम नागरिक के जीवन में निरंतर सुधार के सभी कदम उठाएँगे ।

मैं यह पावती करना चाहूँगा कि इस प्रदेश का विकास जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं हुआ है और मैं इस प्रयास में उनका निरंतर समर्थन की आशा करता हूँ ।

मैं इस भव्य अवसर पर दादरा एवं नगर हवेली की जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूँ ।

.....जय हिन्द ...